India., State Trading Corpn. of India, Indian Oil Corporation Ltd.. are to sign MOU for 1989-90.

The increase in the prices of coal has been necessitated because of increase in the cost of production due to escalation in wages on account of VDA, stores, capital cost etc. The premium on superior grades produced in Raniganj and Korea Rewa fileds has been levied in view of the scarcity of these types of coal in relation to the demand for them.

## छोटी कारों का निर्माण

532. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री पृथ्वी माझी:**

**क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मारुति कारों** की कीमतें पुनः बढ़ा दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मारुति कारों का निर्माण देश में इसलिये प्रारम्भ किया गया था ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमत पर छोटी कार उपलब्ध हो सके;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति मे मारुति उद्योग लिमिटेड के सफल न रहने के क्या कारण हे, और

(ङ) क्या मारुति उद्योग लि० की इस प्रकार की कार बनाने मे असफलता को देखते हुए मध्यमवर्गीय लोगों के लिये इन कारों के वर्तमान मूल्यों की तुलना मे कम कीमत की छोटे साइज की कार बनाये जाने के संबंध मे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

**उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):** (क) और (ख) जी हां। मारुति वाहनों के मूल्य 16-1-89 मे, अमरीकी डालर की तुलना में रुपये में कमी तथा कच्चे माल और खरीदे जाने वाले हिस्से पुर्जों की लागत मे वृद्धि के कारण बढ़ाए गए थे।

(ग) और (घ) मारुति वाहनों के निर्माण के मुख्य उद्देश्यों मे मोटर गाडी उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ ईधन क्षम वाहनों का उत्पादन तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य मोटर वाहनों का उच्च उत्पादन शामिल है। मारुति उद्योग लिमिटेड अपनी परियोजना रिपोर्ट मे दिए गए लक्ष्यों से कही अधिक ईधन क्षम वाहनों को, सारे भारतवर्ष के लोगो को अन्य अच्छे स्थापित माडलों की कीमत से कम मूल्य पर, उपलब्ध कराने में सफल रहा है।

(ङ) सवारी कारों का मूल्य कच्चे माल हिस्से पुर्जों और अन्य अन्तर्वस्तुओं की लागत के साथ-साथ, वित्तीय लेविया जैसे विभिन्न कारणो पर निर्भर करता है।

## मध्य प्रदेश में बिरसिंगपुर पाली में पात विद्युत गृह का निर्माण

533. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री पृथ्वी माझी:**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिरसिंगपुर पाली नामक स्थान पर बन रहे ताप विद्युत गृह के निर्माण की प्रगति किसी न किसी कारण से बहुत धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आरम्भ, उक्त ताप विद्युत गृह के निर्माण में कितने वर्ष लग जाने थे और तब से अब तक, कितने व्यतीत हो चुके?

**ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):** (क) से (ग) संजय गांधी (वीरसिंह पुर) ताप विद्युत परियोजना के 210-210

मेगावाट के यूनिट-एक व यूनिट-दो को प्रारम्भ में क्रमशः वर्ष 1985-86 और 1986-87 मे चालू करने की परिकल्पना की गई थी।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने बायलर सप्लाई के लिए मैसर्स ए०बी०एल० तथा टर्बाइन के लिए मैसर्स भेल को आशय पत्र जारी किए है। मैसर्स ए०बी०एल० ने अक्तूबर, 1986 मे बायलर की सप्लाई रोक दी थी वित्तीय कठिनाइयों के कारण परिसमापन के किया था और इस प्रकार परियोजना के क्रियाकलाप वस्तुतः ठप्प हो गए थे। भूमि अधिग्रहण करने तथा विभिन्न **आनुसंगिक** उपस्कर के लिए आर्डर/सिविल कार्यो के लिए ठेकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने जैसे घटकों से भी परियोजना क्रियान्वयन कार्यक्रम पर कुप्रभाव पडा है।

मैसर्स ए०बी०एल० के पुनरूत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा की गई शुरूआत के परिणामस्वरूप कम्पनी **पुनः बायलर सप्लाइ करने के लिए सहमत हो गई है। मध्य** प्रदेश बिजली बोर्ड ने टर्बोजेनरेटर उपस्कर एवं आनुषंगिकों का निर्माण कार्य जारी रखने के लिए मैसर्स भेल को सलाह दी है। निर्माण कार्यक्रम एवं बायलर **और टर्बोजेनरेटर उपस्करों के डिस्पैच कार्यक्रम को** मद्देनज़र रखते हुए दोनों यूनिटों को अब 1991-92 मे चालू किए जाने की आशा है।

## "ग्रोथ सेन्टर योजना" को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप धीमा उद्योगीकरण

534. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री पृथ्वी माझी:**

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि **जबसे "नो** इण्डस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट" योजना के साथ साथ "ग्रोथ सेन्टर योजना" सरकार द्वारा लागू की गयी है, तब से देश के सबसे पिछड़े "नो इंडस्ट्रीज" जिलों मे उद्योगों को लगाने की गति बहुत धीमी हो गई है और इसके परिणामस्वरूप, ऐसे जिलों का औद्योगिकरण लगभग रूक सा गया है,

(ख) यदि हा, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) "ग्रोथ सेन्टर योजना" के प्रारंभ होने के पश्चात, "नो इंडस्ट्रीज" जिलो मे उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लाइसेंस मंजूर किए गए हैं;

(घ) "ग्रोथ सेन्टर योजना" अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है और कितने लाइसेंस मंजूर किए गए है; और

(ङ) क्या यह सच है कि "ग्रोथ सेन्टर योजना" का लाभ उन जिलो को नहीं मिल रही है जो अपेक्षाकृत सम्पन्न है?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1983 से 1988 के दौरान कुल 540 आशय पत्र तथा 142 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। यदि औद्योगिक लाइसेंस संबंधी कोई बाधा नहीं है तो "उद्योग रहित" जिलो मे औद्योगिक [illegible] के लिए प्राप्त आवेदनों को कभी [illegible] है।

(घ) और (ङ) नई "विकास केन्द्र" याजना हाल ही में घोषित की गयी है तथा विकास केन्द्रों का पता लगाने हेतु राज्य सर [illegible] भेजने के लिए कहा गया है। अत इन विकास केन्द्रो मे परियोजनाएं स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसो का मामला अभी तक नही उठा है।

## Production of Coal

535. SHRI MUKHTHAR SINGH MALIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the estimated Statewise demand and consumption of coal in the country at present;

(b) estimated production of coal at present in the country;

(c) number of new coal mines which have been located in the country during the last one year;